भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3929
25 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः कीटनाशक अवशेष परीक्षण

3929. थी धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटीलः
श्री निलेश ज्ञानदेव संकेः
श्रीमती सुप्रिया सुसेः
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड:
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हेः
श्री संजय दिना पाटीलः
श्री भास्कर मुरलीधर भगरेः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न भागों में रासायनिक उर्यटकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग में मुद्दा क्षरण हुआ है, यदि हां, तो देश में मृदा गुणवत्ता धरण से प्रभावित क्षेत्र कौन-कौन से है, तथा मृदा गुणवता में और अधिक गिरावट को रोकने और श्रीण भूमि को पुनः स्थापित करने के लिए क्या उपाय किए गए है;
(ख) क्या सरकार मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए जैविक खेती को नहाता दे रही है और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम कर रही है और यदि हा तो तरसंबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या मृदा-अनुकूल कृषि पद्धतियों को अपनाने वाले किसानों के लिए कोई प्रोत्साहन या स्निही है और यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने भारतीय मृदा में जैविक कार्बन की मात्रा में कमी का आकलन किया है। यदि हां, तो राबवते अधिक प्रभावित राज्यों सहित तत्संबंधी व्यौरा क्या है।
(ङ) कृषि उत्पादकता पर जैविक पदाथों में कती का प्रभाव क्या है;
(च) मृदा जैविक कार्बन और समग्र मृदा उर्वरता में सुधार के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए है;
(छ) क्या सरकार ने स्थानी मृदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति बनाई है, यदि हा तो नीति के प्रमुख प्रावधान क्या है; और
(ज) मृदा संरक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए कितना वित्तीय आवंटन किया गया है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न भागों में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट आने की चिंता है। इसके समाधान के लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) मृदा परीक्षण आधारित संतुलित और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन की सिफारिश करता है। आईसीएआर ने मिट्टी के स्वास्थ्य और उर्वरता में गिरावट को रोकने के लिए पौधों के पोषक तत्वों के अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों स्रोतों (खाद, जैव-उर्वरक आदि) के संयुक्त उपयोग और स्थान विशेष मिट्टी और जल संरक्षण उपायों का सुझाव दिया है। सरकार मिट्टी के स्वास्थ्य और उर्वरता में सुधार के लिए जैविक खाद और जैव-उर्वरकों के साथ-साथ द्वितीयक और

सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम) को बढ़ावा देने में राज्य सरकारों की सहायता के लिए मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता स्कीम कार्यान्वित कर रही है।

सरकार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर) में परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) की स्कीमों के माध्यम से मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारने के लिए रासायनिक उर्वरक के उपयोग में कमी करने और जैविक खेती को प्रोत्साहित कर रही है। दोनों ही स्कीमें, जैविक खेती से जुड़ें किसानों को समग्र तक सहायता देने पर जोर देती हैं। ये स्कीमें, प्राकृतिक संसाधन आधारित एकीकृत और जलवायु अनुकूल सतत खेती प्रणालियों को बढ़ावा देती हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने और बढ़ाने, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, खेत पर पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण और बाहरी इनपुट पर किसानों की निर्भरता में कमी सुनिश्चित होती है।

पीकेवीवाई स्कीम के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जैविक क्लस्टरों में 3 वर्षों में कुल 31,500 रुपये/हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें से सीधे किसानों को डीबीटी के माध्यम से ऑन-फार्म एवं ऑफ-फार्म जैविक इनपुट के लिए 15,000 रुपये/हेक्टेयर, विपणन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मूल्य संवर्धन आदि के लिए 4,500 रुपये/हेक्टेयर, प्रमाणीकरण एवं अवशेष विश्लेषण के लिए 3,000 रुपये/हेक्टेयर तथा प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के लिए 9,000 रुपये/हेक्टेयर प्रदान किए जाते हैं। एमओवीसीडीएनईआर स्कीम के अंतर्गत, किसान उत्पादक संगठनों के निर्माण, जैविक इनपुट आदि के लिए किसानों को सहायता प्रदान करने हेतु 3 वर्षों में कुल 46,500 रुपये/हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से 15,000 रुपये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सहित ऑन-फार्म/ऑफ-फार्म पर आधारित जैविक इनपुट के लिए किसानों को 32,500 रुपये/हेक्टेयर की दर से सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) से (ज): मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता स्कीम के अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) के माध्यम से कृषि भूमि में जैविक कार्बन की उपस्थिति की नियमित जांच की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत अब तक 24.84 करोड़ एसएचसी सृजित किए गए हैं। मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता स्कीम के अंतर्गत मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार के लिए उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर 7 लाख प्रदर्शन, 93,781 किसान प्रशिक्षण और 7,425 किसान मेले आयोजित किए गए हैं। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) और कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के माध्यम से किसानों को सलाह जारी की जाती है। इसके अलावा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड सलाह जारी करने के लिए 70,002 कृषि सखियों को प्रशिक्षित किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत अब तक 1721 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है।

*****